

गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD, SURAT, LUCKNOW

वर्ष : 16
अंक : 195
दि. 16.11.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा
AHMEDABAD EDITION

म्यांमार से भारत तक फैला 1,000 करोड़ का सुपारी तस्करी सिंडिकेट बेनकाब

नई दिल्ली। म्यांमार से भारत के गुटका और सुपारी बाजार तक फैले करीब 1,000 करोड़ रुपये के कथित तस्करी नेटवर्क का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि यह कारोबार केवल सीमापार सुपारी लाने और बेचने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके लिए फर्जी कंपनियों, डमी मालिकों, कूटरचित बिलिंग, संगठित परिवहन व्यवस्था, कथित प्रोटेक्शन सिंडिकेट और हवाला के जरिए भुगतान का पूरा तंत्र खड़ा किया गया था। म्यांमार से मिजोरम के रास्ते भारत में दाखिल होने वाली सुपारी को कागजों में स्थानीय उत्पादन बताकर देश के अलग-अलग बाजारों तक पहुंचाया जाता था। ईडी की गुवाहाटी और आइजोल इकाइयों ने संयुक्त रूप से पिछले छह महीनों में चार चरणों में 55 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा महाराष्ट्र तक फैले नेटवर्क की कई अहम कड़ियां सामने आई हैं।

जांच एजेंसी के मुताबिक, इस पूरे सिंडिकेट में अलग-अलग जिम्मेदारियां तय थीं। मिजोरम के चम्फाई और जोखावथार क्षेत्र में कथित तौर पर डमी मालिकों के नाम पर तस्करी का माल संभाला जाता था, जबकि असम के सिलचर में बैठे लोग इस व्यवस्था को नियंत्रित करते थे। गुवाहाटी में परिवहन और भंडारण का काम देखने वाले लोग सक्रिय थे तो कोलकाता में फर्जी बिल तैयार करने वाला नेटवर्क काम कर रहा था। दूसरी ओर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ट्रकों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने के नाम पर कथित वसूली की व्यवस्था बनाई गई थी। इस तरह तस्करी से लेकर माल की कागजी पहचान बदलने और अंतिम खरीदार तक पहुंचाने की प्रक्रिया अलग-अलग समूहों के जरिए संचालित होती थी।

ईडी की जांच की शुरुआत वर्ष 2024 में हुई थी। गुवाहाटी हाई कोर्ट की ओर से सुपारी तस्करी के मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद इस पूरे प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की पड़ताल शुरू हुई। इसी आधार पर ईडी की आइजोल इकाई ने धनशोधन की जांच अपने हाथ में ली। जांच के दौरान मिजोरम का जोखावथार तस्करी के प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट के रूप में सामने आया। एजेंसी के अनुसार, मिजोरम में सुपारी का उत्पादन बेहद कम होने के बावजूद वहां से बड़ी मात्रा में सुपारी की आपूर्ति दिखाई जा रही थी। जांच में संदेह जताया गया कि थाईलैंड और इंडोनेशिया से म्यांमार के रास्ते लाई गई सुपारी को मिजोरम में उत्पादित बताकर आगे असम के सिलचर और गुवाहाटी भेजा जाता था।

तियाउ नदी के रास्ते सीमा पार कराई जाती थी सुपारी



तस्करी के इस नेटवर्क में भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली तियाउ नदी का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। यह नदी मिजोरम के चम्फाई जिले के सामने बहती है। जांच एजेंसी के अनुसार, छोटी नावों और कुलियों की मदद से सुपारी को नदी पार कराकर भारतीय क्षेत्र में लाया जाता था। इसके बाद उसे जोखावथार में जमा किया जाता और वहां से आगे भेजने की व्यवस्था होती थी। सीमावर्ती क्षेत्र से माल को निकालने के बाद कागजों में उसकी पहचान बदलने का सिलसिला शुरू होता था। जीएसटी और ई-वे बिल तैयार कर सुपारी को वैध कारोबारी माल के रूप में दिखाया जाता था, ताकि परिवहन के दौरान जांच से बचते हुए उसे सिलचर और फिर गुवाहाटी के बड़े गोदामों तक पहुंचाया जा सके।

गुवाहाटी में बैठे मुख्य संचालकों की भूमिका इस पूरे नेटवर्क में महत्वपूर्ण बताई गई है। उनके नियंत्रण में माल के परिवहन, भंडारण और दस्तावेजों की व्यवस्था संचालित होती थी। गोदामों तक पहुंचने के बाद सुपारी को नए दस्तावेजों के आधार पर आगे भेजने की तैयारी की जाती थी। कई मामलों में माल को नए बैग में पैक किए जाने की बात भी जांच में सामने आई है। इस प्रक्रिया के लिए संगठित लॉजिस्टिक्स कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता था। इससे तस्करी के जरिए लाई गई सुपारी को सामान्य व्यापारिक आपूर्ति का हिस्सा दिखाना आसान हो जाता था।

हर दो-तीन साल में बदल दी जाती थीं कंपनियां

जांच एजेंसी का कहना है कि नेटवर्क से जुड़े लोगों ने जांच से बचने के लिए कंपनियों के नाम और कारोबारी पहचान बदलने का तरीका अपना रखा था। कथित तौर पर हर दो-तीन साल में पुरानी कंपनी बंद कर दी जाती थी और उसी गतिविधि को जारी रखने के लिए नई कंपनी बना ली जाती थी। हालांकि, मोबाइल नंबर, पैन और अन्य दस्तावेजों की जांच में अलग-अलग कंपनियों और उनसे जुड़े लोगों के बीच संबंधों के साक्ष्य मिले। मिजोरम और असम में शामिल आरोपियों के बयानों में भी तस्करी के तौर-तरीकों से संबंधित जानकारियां सामने आने की बात कही गई है।

वित्तीय लेन-देन की पड़ताल में भी बड़े पैमाने पर कारोबार के संकेत मिले हैं। ईडी के अनुसार, नेटवर्क से जुड़ी एक कंपनी के बैंक खाते में ही करीब 876 करोड़ रुपये के क्रेडिट लेन-देन दर्ज पाए गए। इनमें अधिकांश रकम देश के विभिन्न हिस्सों में कारोबार करने वाले सुपारी व्यापारियों से आई थी। एजेंसी इन लेन-देन के स्रोत, वास्तविक कारोबारी गतिविधियों और संबंधित कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है। जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि कथित तस्करी से प्राप्त माल को किस तरह अलग-अलग कारोबारी संस्थाओं के जरिए बाजार में खपाया जाता था।

इस नेटवर्क से जुड़ी कंपनियों की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आए हैं। मैसर्स जय करणी ट्रेडिंग्स और मैसर्स पूर्वोत्तर एग्रो ने पिछले आठ वर्षों के दौरान 400 करोड़ रुपये से अधिक की सुपारी खरीदी थी। इन कंपनियों ने जिन छह बड़ी इकाइयों से खरीद दिखाई, उनमें से पांच के कारोबारी ठिकाने, गोदाम या कार्यालय का पता नहीं चल पाया। जांच के अनुसार, इन्हीं पांच इकाइयों के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक की सुपारी की आपूर्ति दिखाई गई थी। इससे फर्जी या संदिग्ध कारोबारी संस्थाओं के जरिए खरीद-बिक्री के दस्तावेज तैयार किए जाने की आशंका और गहरी हुई।

गोदाम से मिली थी 500 मीट्रिक टन से अधिक सुपारी

इस मामले में पहले भी बड़ी मात्रा में बेहिसाब सुपारी मिलने का घटनाक्रम सामने आ चुका है। जून 2023 में आयकर विभाग ने इसी समूह से जुड़े अमीनगांव स्थित गोदाम पर छापेमारी की थी। इस दौरान वहां से 500 मीट्रिक टन से अधिक बेहिसाब सुपारी बरामद हुई थी। अब ईडी की जांच में सामने आए वित्तीय और कारोबारी संबंधों को उस कार्रवाई से जोड़कर भी देखा जा रहा है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि गोदाम में मिली सुपारी का स्रोत क्या था और उसे किन कंपनियों तथा व्यापारियों के माध्यम से बाजार तक पहुंचाया जाना था।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सुरक्षित रास्ते के नाम पर वसूली

तस्करी के माल को पूर्वोत्तर से देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने में सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अहम भूमिका बताई गई है। उत्तर बंगाल का यह मार्ग बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे बड़े बाजारों तक माल पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। ईडी की जांच के अनुसार, इस रास्ते से हर महीने करीब 100 से 120 ट्रक सुपारी लेकर गुजरते थे। आरोप है कि ट्रांसपोर्टरों से गाड़ियों को सुरक्षित रास्ता देने और जांच से बचाने के नाम पर हर महीने पांच से सात लाख रुपये तक नकद वसूले जाते थे।

इस कथित व्यवस्था के तहत सिंडिकेट से जुड़ी ट्रांसपोर्ट फर्म के नाम वाली पर्चियां ट्रकों को दी जाती थीं। रास्ते में जांच के दौरान इन पर्चियों को दिखाने पर गाड़ियों को आगे जाने दिया जाता था। जांच एजेंसी को आशंका है कि वसूली गई रकम का एक हिस्सा रास्ते में तैनात कुछ अधिकारियों तक भी पहुंचाया जाता था। बदले में ट्रकों की आवाजाही और जांच से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती थीं। हालांकि, इस कथित वसूली व्यवस्था में शामिल लोगों और उनकी भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा।

फर्जी बिलिंग से लेकर हवाला भुगतान तक के सुराग

पश्चिम बंगाल में भी इस नेटवर्क की महत्वपूर्ण कड़ी सामने आई है। जांच के अनुसार, कोलकाता में फर्जी बिल तैयार करने वाला समूह सक्रिय था, जो तस्करी की सुपारी को वैध व्यापारिक माल के रूप में दर्शाने के लिए दस्तावेज तैयार करता था। इसके सदस्य बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर भी सक्रिय रहते थे। इन दस्तावेजों के सहारे माल को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने और कारोबारी लेन-देन को सामान्य व्यापार की शक्ल देने का प्रयास किया जाता था।

ईडी को म्यांमार में बैठे तस्करों तक हवाला के जरिए रकम पहुंचाए जाने के साक्ष्य मिलने की भी बात कही गई है। इससे जांच का दायरा केवल सुपारी की अवैध आवाजाही तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि विदेश में बैठे कथित संचालकों तक धन पहुंचाने के तरीके भी जांच के केंद्र में आ गए हैं। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि तस्करी से अर्जित रकम किन माध्यमों से एकत्र की जाती थी, किसके जरिए सीमा पार भेजी जाती थी और इसमें किन लोगों तथा कारोबारी संस्थाओं की भूमिका थी।

एसआईआर में नाम कटने पर नहीं होगी कार्रवाई, फॉर्म-6 से फिर बनेगा वोटर कार्ड

नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से नाम हट जाने के बाद दोबारा पंजीकरण कराने को लेकर चिंतित लोगों के लिए राहत की खबर है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों का नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किसी कारणवश कट गया है, वे फॉर्म-6 भरकर फिर से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। ऐसा करने मात्र से उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयोग ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। इससे उन मतदाताओं की आशंका दूर होने की उम्मीद है, जो पहले से पंजीकृत होने के बावजूद दोबारा आवेदन करने में कानूनी उलझन की आशंका से पीछे हट रहे थे।

दरअसल, फॉर्म-6 का इस्तेमाल सामान्य तौर पर पहली बार मतदाता बनने वाले नागरिकों के पंजीकरण के लिए किया जाता है। इस फॉर्म में आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि उसका नाम पहले किसी भी मतदाता सूची में दर्ज नहीं रहा है। ऐसे में एसआईआर के दौरान नाम कट जाने वाले पुराने मतदाताओं के सामने यह सवाल खड़ा हो गया था कि यदि वे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरते हैं तो क्या उनकी घोषणा गलत मानी जाएगी और क्या उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसी आशंका के चलते कई लोग आवेदन करने से हिचक रहे थे। इस मामले में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 का भी उल्लेख किया जा रहा था। इस धारा के तहत मतदाता पंजीकरण से संबंधित आवेदन या घोषणा में जानबूझकर गलत जानकारी देने पर कार्रवाई का प्रावधान है। चूंकि फॉर्म-6 में पहले किसी मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं होने की घोषणा शामिल है, इसलिए पहले से मतदाता रह चुके लोगों के लिए इसे भरना असमंजस का कारण बन गया था। उन्हें डर था कि पुराने पंजीकरण की जानकारी सामने आने पर उनके खिलाफ गलत घोषणा करने का मामला बन सकता है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में इस आशंका को दूर करते हुए कहा है कि केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी कि वह पहले मतदाता सूची में पंजीकृत था और अब नाम दोबारा जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर रहा है। हालांकि, आयोग ने इसके साथ कुछ आवश्यक शर्तें भी स्पष्ट की हैं। आवेदक का नाम किसी दूसरे संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए। साथ ही, आवेदन में दी गई घोषणा और जानकारी कानून के अनुरूप होनी चाहिए। इस तरह आयोग ने दोबारा पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है, ताकि पात्र मतदाता कानूनी कार्रवाई के डर के बिना अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकें।

आयोग ने यह भी बताया है कि एसआईआर के दौरान छूट गए मतदाताओं के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कराने के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देना है, जिनका किसी कारण से फॉर्म जमा नहीं हो पाया या जो पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन अधिकारियों तक अपनी जानकारी नहीं पहुंचा सके। आयोग के अनुसार, मतदाता सूची में पात्र नागरिकों का नाम शामिल रहना जरूरी है और इसके लिए छूटे हुए लोगों को आवेदन की सुविधा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की बात भी कही है। आयोग ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट यानी एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत छह नवंबर, 2026 को जारी निर्देश में एसआईआर वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को छूटे हुए मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। चुनाव आयोग के इस स्पष्टीकरण से उन लोगों को राहत मिल सकती है, जिनका नाम पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से हट गया है और वे दोबारा पंजीकरण कराने को लेकर असमंजस में हैं। आयोग ने यह साफ कर दिया है कि पहले मतदाता रह चुके होने के कारण फॉर्म-6 भरना अपने आप में अपराध नहीं माना जाएगा।

कांग्रेस ने 26 नवंबर का 'चलो दिल्ली' कार्यक्रम टाला, राज्यों में निकालेगी संविधान रक्षा मार्च

नई दिल्ली। कांग्रेस ने 26 नवंबर को प्रस्तावित अपने 'चलो दिल्ली' कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। पार्टी ने अब इस दिन देशभर में सभी राज्यों की राजधानियों में 'संविधान रक्षा मार्च' आयोजित करने का फैसला किया है। इसे पार्टी की विरोध रणनीति में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस और विपक्षी दल पहले से ही मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों तथा चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसी मुद्दे पर विपक्ष ने हाल ही में दिल्ली में बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी किया था। अब 26 नवंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम के जरिए पार्टी इस विरोध को राज्य स्तर तक पहुंचाने की तैयारी में है।

कांग्रेस का 'चलो दिल्ली' कार्यक्रम 26 नवंबर को आयोजित होना था, लेकिन पार्टी ने इसे फिलहाल टालने का निर्णय लिया है। इसके स्थान पर संविधान रक्षा मार्च निकालने की योजना बनाई गई है। ये मार्च सभी राज्यों की राजधानियों में आयोजित होंगे। पार्टी का उद्देश्य संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाना तथा मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराना है। कार्यक्रम की बदली हुई रूपरेखा के तहत अब विरोध का केंद्र केवल दिल्ली तक सीमित न रहकर देश के विभिन्न राज्यों में होगा।



इससे पहले एक नवंबर को विपक्षी गठबंधन INDIA ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली आयोजित की थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाना था। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने देशव्यापी अभियान चलाने की बात कही थी।

रामलीला मैदान में आयोजित रैली से पहले 31 अक्टूबर को राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक 'महाभियोग' कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इसके बाद एक नवंबर की रैली में विपक्ष के कई प्रमुख नेता एक मंच पर दिखाई दिए। इनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी, सांसद अभिषेक बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी. राजा, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल थे।

रैली का मार्च मिंटो रोड-कनॉट प्लेस जंक्शन से शुरू होकर रामलीला मैदान की ओर बढ़ा था। यह आयोजन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विपक्ष के व्यापक अभियान का हिस्सा था। इसमें शामिल नेताओं ने मतदाता सूची की शुद्धता, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखी थीं। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मताधिकार के लिए गंभीर विषय है।

अब 26 नवंबर को राज्यों की राजधानियों में प्रस्तावित संविधान रक्षा मार्च के जरिए कांग्रेस इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएगी। पार्टी ने दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम को टालकर विरोध को व्यापक स्तर पर आयोजित करने का रास्ता चुना है। हालांकि, 'चलो दिल्ली' कार्यक्रम को स्थगित करने के पीछे की विस्तृत वजह सामने नहीं आई है। फिलहाल पार्टी की नई योजना के तहत संविधान रक्षा, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े सवाल राजनीतिक बहस के केंद्र में बने रहने की संभावना है।

क्वाड के निष्क्रिय होने की खबरों को अमेरिका ने बताया हास्यास्पद

नई दिल्ली। अमेरिका ने उन मीडिया रिपोर्टों को सिरे से खारिज किया है, जिनमें दावा किया गया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में चार देशों के रणनीतिक समूह क्वाड की सक्रियता कमजोर पड़ गई है और संगठन अब लगभग निष्क्रिय स्थिति में पहुंच गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ऐसी खबरों को हास्यास्पद बताते हुए कहा है कि क्वाड के भीतर उच्चस्तरीय बातचीत और सहयोग लगातार जारी है। विदेश विभाग के वैश्विक सार्वजनिक मामलों के सहायक सचिव डायलन जॉनसन ने पोलिटिको की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो पिछले दो वर्षों में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ पांच औपचारिक बैठकें कर चुके हैं। इनमें से तीन बैठकें पिछले छह महीनों के दौरान हुई हैं। अमेरिका के इस बयान से स्पष्ट है कि वह क्वाड की प्रासंगिकता और सक्रियता को लेकर उठ रहे सवालों को स्वीकार करने के बजाय संगठन की निरंतरता पर जोर दे रहा है।



क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक संपर्क और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना इस समूह के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण क्वाड की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इन रिपोर्टों में संगठन के भविष्य और चारों देशों के बीच सहयोग की गति को लेकर सवाल उठाए गए थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि संगठन के विभिन्न स्तरों पर नियमित संवाद जारी है और इसे निष्क्रिय बताना तथ्यों के विपरीत है।

जॉनसन के मुताबिक, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पद संभालने के बाद अपनी पहली आधिकारिक कॉल क्वाड से जुड़े विषय पर की थी। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन के शेरपा स्तर पर नियमित मासिक बातचीत और बैठकें होती रही हैं। शेरपा स्तर की बातचीत को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से सदस्य देश विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्राथमिकताओं और प्रस्तावित पहलों को आगे बढ़ाते हैं। विदेश विभाग का कहना है कि केवल शिखर बैठकों की संख्या के आधार पर संगठन की सक्रियता का आकलन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर कई स्तरों पर लगातार काम चलता रहता है। अमेरिका ने यह भी संकेत दिया है कि वह क्वाड नेताओं की अगली शिखर बैठक आयोजित कराने की दिशा में प्रयास कर रहा है। जॉनसन के अनुसार, वाशिंगटन अगले सप्ताह मनीला में होने वाली आसियान बैठकों के दौरान क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप देने के लिए काम कर रहा है। यदि इस दिशा में सहमति बनती है तो चारों देशों के शीर्ष नेतृत्व को एक मंच पर लाने का रास्ता साफ हो सकता है। इससे संगठन की भावी प्राथमिकताओं और सहयोग के एजेंडे पर चर्चा का अवसर मिलेगा।

पिछले छह महीनों में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की तीन बैठकें हुई हैं। इनमें मई 2026 में नई दिल्ली में हुई बैठक, जुलाई में मनीला में आयोजित बैठक और हाल ही में जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अटलांटा में हुई मुलाकात शामिल है। अमेरिकी पक्ष इन बैठकों को इस बात के प्रमाण के रूप में पेश कर रहा है कि क्वाड का संवाद तंत्र सक्रिय है। हालांकि, बैठकों की निरंतरता के बावजूद संगठन के एजेंडे पर ठोस प्रगति को लेकर कुछ सवाल भी बने हुए हैं।

अटलांटा में हुई बैठक में उन मुद्दों पर फिर चर्चा हुई, जिन्हें पांच महीने पहले नई दिल्ली की बैठक में उठाया गया था। इनमें स्वतंत्र और खुला हिंद-प्रशांत क्षेत्र, समुद्री सुरक्षा, सीमा पार अपराधों से निपटना, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करना, मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन तथा उभरती तकनीकों में सहयोग जैसे विषय शामिल थे। ये मुद्दे क्वाड के साझा रणनीतिक और आर्थिक एजेंडे का हिस्सा हैं। चारों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और क्षेत्रीय चुनौतियों से मिलकर निपटने की प्रतिबद्धता जताते रहे हैं। लेकिन एक ही तरह के विषयों पर बार-बार चर्चा होने के कारण यह सवाल उठता है कि इन बैठकों के निष्कर्षों को जमीन पर लागू करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है।

नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की घोषणा भी की गई थी। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना था। इन खनिजों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक तकनीकी उपकरणों के निर्माण में होता है। इनके खनन, प्रसंस्करण और रीसाइक्लिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए चारों देशों ने सरकारी और निजी क्षेत्र से 20 अरब डॉलर तक जुटाने का इरादा जताया था। इस पहल को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता और उनकी आपूर्ति पर नियंत्रण वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा तकनीकी प्रतिस्पर्धा से जुड़ा विषय बन चुका है।

अटलांटा बैठक में इस पहल के तहत ई-कचरे से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति पर काम आगे बढ़ाने का उल्लेख किया गया। इसके साथ ही अमेरिका की ओर से भारत और आसियान देशों में संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक करोड़ डॉलर देने की बात भी सामने आई। हालांकि, घोषित निवेश की व्यापक संभावनाओं के बावजूद बड़ी परियोजनाओं को अंतिम रूप देने, वास्तविक निवेश सुनिश्चित करने और सहयोग के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित करने से जुड़े कई फैसले अभी लंबित हैं। ऐसे में पहल की घोषणा और उसके व्यावहारिक परिणामों के बीच की दूरी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। क्वाड की सक्रियता को लेकर उठे सवालों के बीच अमेरिकी विदेश विभाग का यह बयान संगठन के प्रति वाशिंगटन की प्रतिबद्धता दिखाने का प्रयास है। अमेरिका बैठकों, नियमित संवाद और प्रस्तावित शिखर सम्मेलन को अपनी दलील के आधार के रूप में सामने रख रहा है। दूसरी ओर, संगठन की वास्तविक प्रभावशीलता का आकलन केवल बैठकों की संख्या से नहीं, बल्कि साझा फैसलों के क्रियान्वयन, निवेश और क्षेत्रीय स्तर पर दिखाई देने वाले परिणामों से होगा।



संपादकीय

ट्रंप ताऊ को ज्ञानेश कुमार की याद, लेकिन बहुत देर हो गई!

राजनीति भी बड़ी अजीब चीज है जनाब! यहां किसी की अहमियत तब तक समझ में नहीं आती, जब तक उसकी जरूरत न पड़ जाए। जरूरत पड़ते ही वही शख्स खास हो जाता है, जिसकी चर्चा कल तक अपने ही लोग अलग-अलग वजहों से कर रहे होते हैं। अब ट्रंप ताऊ को ही लीजिए। लगता है कि उन्हें ज्ञानेश कुमार की खूबियां समझने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। जब तक उनकी प्रतिभा याद आई, तब तक शायद परिस्थितियां बदल चुकी थीं। ऐसे में यही कहावत याद आती है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। या फिर यूं कह लीजिए कि का वर्षा जब कृषि सुखाने! हमारे यहां तो प्रतिभाओं की कद्र करने का अपना अलग ही तरीका है। घर में कोई कितना भी गुणवान क्यों न हो, उसकी अहमियत अक्सर नहीं समझी जाती। घर की मुर्गी दाल बराबर और घर का जोगी जोगड़ा। लेकिन जैसे ही बाहर का कोई व्यक्ति उसकी तारीफ कर दे, हम भी उसकी खूबियां गिनाने लगते हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि अपनी प्रतिभाओं को पहचानने के लिए हमें विदेशी प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती है। हालांकि, इस बार मामला थोड़ा उलटा है। यहां अपने देश में ज्ञानेश कुमार को लेकर राजनीतिक बहस जारी है और उधर ट्रंप ताऊ की दिलचस्पी की चर्चा होने लगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ज्ञानेश कुमार में ऐसी कौन-सी खासियत है, जो ट्रंप साहब को आकर्षित कर सकती है? अमेरिका तो खुद को दुनिया की प्रतिभाओं का बड़ा केंद्र मानता है। वहां बड़े-बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं, जो किसी की योग्यता और क्षमता पहचानने का दावा करते हैं। सिलिकॉन वैली में भारतीयों ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। दुनिया की नामी कंपनियों में भारतीय मूल के लोगों की धाक है। फिर भी अगर किसी भारतीय चुनाव आयुक्त की चर्चा अमेरिकी राजनीतिक गलियारों तक पहुंचती है तो इसे भी कम दिलचस्प बात नहीं कहा जा सकता। वैसे चुनाव आयुक्तों का इतिहास देखें तो हर किसी को टीएन शेषन जैसी प्रसिद्धि नहीं मिली। शेषन ऐसे चुनाव आयुक्त थे, जिनके नाम से ही राजनीतिक दलों में हलचल मच जाती थी। उनके बारे में मशहूर था कि वे नाश्ते में नेताओं को खा जाते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की शक्तियों का ऐसा इस्तेमाल किया कि नेताओं को चुनावी नियमों का पालन करना ही पड़ा। अब ज्ञानेश कुमार भी लगातार सुर्खियों में हैं, लेकिन उनके चर्चित होने की वजह कुछ और है। विपक्षी दलों का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नाम हटाए जा रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को लगातार घेर रहा है और ज्ञानेश कुमार उसके निशाने पर हैं। अब देखिए न, शेषन के समय नेता उनसे डरते थे और आज विपक्षी नेता ज्ञानेश कुमार से खार खाए बैठे हैं। दोनों के बीच तुलना भी अपने आप में दिलचस्प है। एक ने चुनाव आयोग की सख्ती से पहचान बनाई तो दूसरे के कार्यकाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। हालांकि, किसी भी चुनाव आयुक्त की असली कसौटी राजनीतिक दलों की नाराजगी या प्रशंसा नहीं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता होती है। लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी यह भरोसा भी है कि किसी पात्र मतदाता का नाम अनुचित तरीके से न हटे। उधर ट्रंप ताऊ की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। अमेरिका में चुनावी राजनीति का गणित भी कम उलझा हुआ नहीं है। वहां जनता को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। ट्रंप भी अपने अंदाज में अमेरिकी मतदाताओं को पांच हजार डॉलर का डिविडेंड देने की बात कर चुके हैं। अब उन्हें भी शायद यह समझ में आ रहा होगा कि चुनाव जीतने के लिए केवल भाषण और बड़े-बड़े दावे काफी नहीं होते, जनता की जेब और उसकी उम्मीदों का भी ध्यान रखना पड़ता है। भारत में चुनावी राजनीति ने इस मामले में कई दिलचस्प प्रयोग देखे हैं। महिलाओं के खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाने वाली योजनाओं ने महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार सहित कई राज्यों में राजनीतिक बहस को नया आयाम दिया है। इन योजनाओं को लेकर सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाता है तो विपक्ष इनके आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पर सवाल उठाता है। मगर इतना जरूर है कि मतदाताओं तक सीधे लाभ पहुंचाने की रणनीति अब चुनावी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। ट्रंप ताऊ को भी शायद इसी तरह के प्रयोगों में उम्मीद की कोई किरण दिखाई दी हो। उन्हें लगा होगा कि जब भारत में ऐसी योजनाएं राजनीतिक समीकरण बदल सकती हैं तो अमेरिका में भी आर्थिक लाभ का वादा मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है।

एआई के सवाल और बापू के जवाब

> गांधीजी ने चरखे को केवल सूत कातने का यंत्र नहीं, आत्मनिर्भरता और गरिमा का प्रतीक बनाया था। एआई भी केवल एक यंत्र या तकनीक है। वह हमें निर्भर, विभाजित और प्रकृति-विरोधी बनाएगी या आत्मनिर्भर, समावेशी और संयमी—यह मशीन नहीं, हमारा...



गांधीजी ने चरखे को केवल सूत कातने का यंत्र नहीं, आत्मनिर्भरता और गरिमा का प्रतीक बनाया था। एआई भी केवल एक यंत्र या तकनीक है। वह हमें निर्भर, विभाजित और प्रकृति-विरोधी बनाएगी या आत्मनिर्भर, समावेशी और संयमी—यह मशीन नहीं, हमारा विवेक तय करेगा।

एआई पर दुनिया हरकत में है। एक तरफ अवसर हैं, दूसरी तरफ संकट। अवसर तकनीक से पैदा हुई तेजी का है, समस्या उसी तकनीक से सत्य, पहचान, नकल और रोजी-रोजगार को लेकर पैदा होते संकट की है। डीपफेक से लेकर छिनती नौकरियों और प्यासे डेटा सेंटरों तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जो दिक्कतें खड़ी की हैं, उनका इलाज केवल कानूनों में नहीं, उन मूल्यों में भी है, जिन्हें समाज ने, दूरदर्शी मार्गदर्शकों ने और सुधारकों ने दशकों या शायद सदियों पहले गढ़ा था। जैसे गांधीजी ने मशीनी सभ्यता को लेकर जो कुछ कहा था, ऐसा लगता है कि एआई के इस दौर में वैसे ही सवाल हमारे सामने हैं। तो क्या गांधी-दर्शन एआई की समस्याओं का हल भी है? आम धारणा है कि महात्मा गांधी मशीनों के धुर विरोधी थे। 1909 में 'हिंद स्वराज' में उन्होंने मशीनी सभ्यता की तीखी आलोचना की थी और चरखा उनकी पहचान बन गया था। पर यह आधा सच है। 1925 में उन्होंने 'यंग इंडिया' में साफ लिखा कि उनका ऐतराज मशीन से नहीं, मशीन के प्रति उन्माद से है। उसी लेख में उन्होंने सिलाई-मशीन को उन उपयोगी चीजों में गिना था, जिनका आविष्कार काम को सरल और बेहतर करने के क्रम में हुआ था। गांधी की चिंता यह थी कि मशीन किसके हित में चलती है। क्या वह मनुष्य का हित करती है या उसे बेकार, आश्रित और शोषित बनाती है? आज, जब एआई निबंध और शोध-पत्र लिख रही है, रोगों की पहचान कर रही है, फसल चक्र का सटीक अनुमान लगा रही है और चेहरे, आवाजें, वीडियो तक गढ़ रही है, गांधी का यही दर्शन पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। एआई कोई साधारण मशीन या तकनीक नहीं है। वह ऐसा पहला औजार है, जो हाथ के साथ-साथ दिमाग के काम में दखल दे रहा है। इसलिए उसके प्रति न तो अंधी आस्था ठीक है, न ही अंधा भय। जरूरत एक कसौटी बनाने की है, जिसमें गांधी के विचार काम आ सकते हैं।

गांधीजी ने 'यंग इंडिया' में ऐसे ही प्रश्नों पर विचार करते हुए सात पापों की सूची दी थी। उनमें से तीन आज के एआई-दौर में एकदम सटीक प्रतीत होते हैं: मानवता के बिना विज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार और चरित्र के बिना ज्ञान। मानवता के बिना विज्ञान वह है, जब तकनीक की होड़ इस सवाल को पीछे छोड़ दे कि उसका असर सबसे कमजोर व्यक्ति पर क्या होगा। नैतिकता के बिना व्यापार वह है, जब लोगों का डेटा, ध्यान (अटेंशन) और निजता (प्राइवेसी) मुनाफे का कच्चा माल बन जाएं। और चरित्र के बिना ज्ञान वह है, जब हर प्रश्न का उत्तर एक क्लिक पर मिले, लेकिन उसे परखने का विवेक न बचे।

गांधीजी के लिए सत्य ही ईश्वर था। एआई-युग में सत्य पर दोहरा संकट है। एक ओर डीपफेक हैं, जिनमें किसी का भी चेहरा और आवाज बनाकर सच का झांसा या आभास देने वाला झूठ गढ़ा जा सकता है। दूसरी ओर चैटबॉट हैं, जो कभी-कभी पूरे आत्मविश्वास से ऐसे तथ्य और संदर्भ रच देते हैं, जो हकीकत में होते ही नहीं हैं। डीपफेक और चैटबॉट का 'मतिभ्रम' सत्य पर हमला है। इनमें से एक से जान-बूझकर झूठ गढ़ा जा सकता है, दूसरे से मशीन के जरिए अनजाना असत्य पैदा किया जा सकता है। गांधी का सत्याग्रह यह सबक देता है कि सत्य की रक्षा केवल कानून से नहीं, नागरिक के आग्रह से होती है, यानी हर सूचना को परखने, स्रोत पूछने और झूठ को आगे नहीं बढ़ाने के आग्रह से।

अहिंसा की कसौटी पर भी एआई के कई सवालों को परखा जा सकता है। युद्ध में स्वायत्त हथियार, जो संकेत या निर्णय के लिए इंसानी दखल का इंतजार भी न करें, गांधी-दर्शन के हिसाब से सबसे बड़ा नैतिक प्रश्न होते। पर हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती। किसी महिला की नकली और अश्लील छवि बनाना, ऑनलाइन उत्पीड़न या पक्षपाती एल्गोरिद्म से किसी को जरूरी कर्ज या नौकरी से वंचित करना भी हिंसा के ही रूप हैं, भले ही उसमें रक्त न बहे। और प्रकृति के प्रति हिंसा भी तब इसी श्रेणी में आती है, जब विशाल डेटा सेंटर भारी बिजली और पानी की खपत करें। वह भी तब, जब शहर, गांव-कस्बे पीने के पानी को तरस रहे हों।

स्वराज गांधी के लिए सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि वह आत्म-नियंत्रण का उपाय भी था। आज की तकनीक का कारोबारी मॉडल अक्सर हमारे ध्यान पर कब्जा करने पर टिका है। इसमें अंतहीन स्क्रॉल, लगातार सूचनाएं और ऐसे एआई-सहायक (एजेंट) बनाने पर जोर है, जो सोचने की मेहनत से ही छुटकारा दिलाते हैं। विद्यार्थी अगर हर उत्तर मशीन से लें, तो अभ्यास की गति भले बढ़ जाए, लेकिन समझ (मेधा) का अंततः पतन ही होगा। अपने मन-मस्तिष्क पर नियंत्रण हासिल करना एआई-युग का सबसे कठिन और जरूरी स्वराज है। राष्ट्र के स्तर पर स्वदेशी का अर्थ है भारतीय भाषाओं और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप एआई, न कि हर समाधान के लिए बाहरी निर्भरता। इसी तरह, गांधी का ट्रस्टीशिप (न्यासिता) संबंधी विचार कहता है कि धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वामी नहीं, समाज की ओर से उसका ट्रस्टी (न्यासी) है। एआई के युग में सबसे बड़ी संपत्ति डेटा और कंप्यूटिंग की ताकत है, जो कुछ गिनी-चुनी कंपनियों और देशों के पास सिमटती जा रही है। लोगों की आवाजों, चित्रों और शब्दों से बने और प्रशिक्षित हुए एआई पर समाज का हक होना चाहिए। उसके फायदे भी उन लोगों तक पहुंचने चाहिए, जिनके डेटा से वह बना है।

गांधीजी शारीरिक श्रम को सम्मान और महत्व देते थे। उनकी व्यवस्था में उत्पादन जन-समूह के हाथों से हो, केवल विशाल कारखानों से नहीं। एआई इधर जब क्लर्की और दफ्तरी कामों को बदल रहा है, तब सवाल यह है कि बचा हुआ समय और लाभ किसके हिस्से में जाएगा। क्या श्रमिक को नया कौशल और सम्मानजनक काम मिलेगा, या वह हाशिये पर धकेल दिया जाएगा? गांधी-दर्शन हमें एआई से मुंह मोड़ने को नहीं कहता है। वर्ष 1929 में उनसे जुड़े अखिल भारतीय चरखा संघ ने एक बेहतर, हल्का और अधिक उत्पादक चरखा बनाने पर एक लाख रुपये के पुरस्कार की घोषणा की थी, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। गांधीजी नवाचार के विरोधी नहीं थे, लेकिन मंशा यह थी कि नवाचार गांव, गरीब और श्रमिक के काम आए।

संतुलन के लिए गांधीजी ने अपने अंतिम दिनों में एक 'जंतर' दिया था। इसमें उन्होंने सूत्रबद्ध विचार पिरोते हुए कहा था कि जब भी संदेह हो, सबसे गरीब और कमजोर का चेहरा याद करो और खुद से पूछो कि तुम्हारा अगला कदम उसके लिए कितना उपयोगी होगा। इस जंतर को चार व्यावहारिक सवालों में बदला जा सकता है, जिन पर हर एआई प्रणाली को परखा जाए। पहला, क्या यह तकनीक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है—उसकी भाषा में, उसके साधनों में? दूसरा, क्या यह सत्य और पारदर्शिता का सम्मान करती है, यानी क्या लोग यह जान सकते हैं कि निर्णय मशीन ने लिया और क्यों? तीसरा, क्या यह मनुष्य के स्वराज को बढ़ाती है या उसकी निर्भरता को, यानी क्या यह सोचने में मदद करती है या फिर विवेक और सोच-समझ की प्रक्रिया को कुंद करती है? चौथा, इसकी कीमत प्रकृति और श्रमिक ने कितनी चुकाई है?

भारत के एक नागरिक के तौर पर हमारे पास इन सवालों को केंद्र में रखने का अवसर भी है और नैतिक अधिकार भी। जिस देश ने दुनिया को अहिंसा और सत्याग्रह का विचार दिया, वह एआई के युग में 'मानव-केंद्रित' तकनीक का सबसे विश्वसनीय स्वर बन सकता है, बशर्ते हम खुद इन कसौटियों पर खरे उतरें।

प्रेरणा

बेटी की खुशियों के नाम पर पिता की जिंदगी का सौदा कब तक?

बेटी जवान हो चुकी थी। उम्र के साथ उसके सपनों ने भी आंखें खोलनी शुरू कर दी थीं। वह कोई बहुत सुंदर या नाजुक कली नहीं थी, बल्कि गरीबी और अभावों में पली एक दुबली-पतली लड़की थी। चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में एक छोटा-सा संसार बसाने की उम्मीद।

पिता दीनानाथ हाल ही में लाला की फैक्टरी से चपरासी की नौकरी पूरी कर सेवानिवृत्त हुआ था। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली खुशी उसके चेहरे पर कहीं दिखाई नहीं देती थी। हाथ खाली थे और जिम्मेदारियां अब भी सिर पर खड़ी थीं। फटी बनियान से झांकती हड्डियां और थका हुआ चेहरा उसकी आर्थिक स्थिति का पूरा हाल बता रहे थे। सबसे बड़ी चिंता जवान बेटी की शादी थी।

मां भी कभी घरों में चौका-बर्तन करके परिवार का सहारा बनती थी, लेकिन अब बीमारी ने उसे बिस्तर पर ला दिया था। दीनानाथ की थोड़ी-बहुत जमा पूंजी उसके इलाज में खर्च हो चुकी थी। एक छोटा भाई जरूर था, मगर उसने गरीबी में घिरे बड़े भाई से पहले ही किनारा कर लिया था। ऐसे में दीनानाथ के पास किसी से मदद मांगने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था।

काफी कोशिशों के बाद बेटी का रिश्ता एक सरकारी नौकरी करने वाले युवक से तय हुआ। नौकरी भी पक्की थी। बिचौलिये ने भरोसा दिलाया था कि लड़के वालों की कोई मांग नहीं है। दीनानाथ और उसकी पत्नी ने इसे भगवान का आशीर्वाद समझा। उन्हें लगा कि चलो, बेटी का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहेगा।

लेकिन रिश्ता तय होने के बाद शादी की तैयारियों के साथ खर्चों का पहाड़ भी सामने आने लगा। मां ने कहा कि बेटी को खाली हाथ विदा थोड़े ही करेंगे। कुछ जेवर, कपड़े, अलमारी, पलंग और घर-गृहस्थी का जरूरी सामान तो देना ही पड़ेगा। रिश्तेदारों के कपड़े और मेहमानों की खातिरदारी का खर्च अलग था। छोटी-सी जमा पूंजी का हिसाब लगाया तो कुछ भी पूरा होता दिखाई नहीं दिया।

मां ने अपनी बचाकर रखी रकम बेटी को देते हुए कहा, 'बेटा, इससे अपने कपड़े बनवा लेना। मेरे पास चांदी का एक सेट है, वह भी तुम्हें दे दूंगी। अब मुझे इसकी क्या जरूरत है।' यह कहते-कहते उसकी आंखें भर आईं। बेटी मां का दर्द समझ रही थी। उसे यह भी मालूम था कि पिता हर दिन किसी नए इंतजाम की चिंता में घुलता जा रहा है।

एक दिन बिचौलिया नई खबर लेकर आया। लड़के वालों का कहना था कि आजकल फ्रिज और एलईडी टीवी देना तो आम बात है। इससे दोनों परिवारों की इज्जत बनी रहती है। दीनानाथ ने सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अभी तक शादी का सामान्य खर्च ही नहीं जुट पा रहा था, अब यह नई मांग कहां से पूरी होगी?

वह बीड़ी पर बीड़ी सुलगाता रहा। मन में सवाल उठता रहा कि आखिर किसके सामने हाथ फैलाए? क्या गिरवी रखे? संकरी गली में बना डेढ़ कमरे का पुराना मकान ही तो उसकी पूरी दुनिया था।

कुछ दिन बीते ही थे कि बिचौलिया फिर आ पहुंचा। इस बार संदेश था कि लड़के को बाइक चाहिए। किस्तों पर मिल जाएगी, आखिर बेटी भी तो उस पर घूमेगी! बाइक की कीमत सुनकर दीनानाथ का सिर चकरा गया। साठ-पैंसठ हजार रुपये कहां से आएंगे? उसकी छाती में जकड़न बढ़ने लगी। मां की आंखों से आंसू बहने लगे और घर में सन्नाटा छा गया।

बेटी सब कुछ देख रही थी। उसके सपने अब फ्रिज, टीवी और बाइक की मांगों के नीचे दबते जा रहे थे। वह सोच रही थी कि जिस घर में उसे जीवनसाथी बनकर जाना है, वहां उसकी कीमत आखिर इन सामानों से क्यों तय की जा रही है? क्या सरकारी नौकरी करने वाले युवक को पत्नी चाहिए या दहेज से भरा घर?

शादी में अब डेढ़ महीना ही बचा था। हर दिन परिवार की परेशानी बढ़ रही थी। इसी बीच बिचौलिये ने फोन करके पूछा, 'सब इंतजाम हो गया न?'

दीनानाथ का गुस्सा फूटने को तैयार था। मन हुआ कि कह दे, हां, सब इंतजाम कर दिया है, उनके कफन का भी! लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी बेटी ने पिता से कहा, 'पिताजी, मेरी शादी के लिए आप अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाइए। मुझे ऐसे घर नहीं जाना, जहां मेरे माता-पिता की हैसियत सामान से आंकी जाती हो।'

दीनानाथ ने फोन उठाया और बिचौलिये से साफ कह दिया, 'उन्हें बता देना, अपना इंतजाम कहीं और कर लें। हम अपनी बेटी का सौदा नहीं करेंगे।'

मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में बेबसी के साथ बेटी के फैसले का गर्व भी था। शादी टूटने का दुख जरूर था, मगर उससे बड़ा दुख उस रिश्ते में बंध जाने का होता, जहां हर खुशी की कीमत मां-बाप की गरीबी से वसूली जाती।

दीनानाथ ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। उसे महसूस हुआ कि उसके पास भले ही धन-दौलत नहीं, लेकिन बेटी के रूप में आत्मसम्मान की अनमोल पूंजी जरूर है। घर में अब भी आर्थिक तंगी थी, भविष्य की राह आसान नहीं थी, मगर एक बात तय हो चुकी थी—बेटी की खुशियों के लिए अब किसी की नाजायज शर्त स्वीकार नहीं होगी।

समाज में दहेज की मांग को परंपरा और प्रतिष्ठा का नाम देने वाले लोग शायद यह नहीं समझते कि उनकी छोटी-छोटी मांगें किसी गरीब परिवार की पूरी जिंदगी तबाह कर देती हैं। शादी दो लोगों के जीवन का मिलन है, सामान की खरीद-बिक्री नहीं। जिस रिश्ते की शुरुआत ही मांगों और शर्तों से हो, उसमें अपनापन कहां से आएगा?

क्या योगी की हैट्रिक में अड़ंगा लगा पायेंगे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद?

नमस्कार प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में इस सप्ताह यूपी चुनावों पर खास फोकस किया गया। दरअसल हमारे पाठकों और दर्शकों ने जो सवाल पूछे उनका लब्बोलुआब यह था कि यूपी में 2027 की सियासी जंग में किसके पाले में जाएगा सत्ता का ताज? तो आइये सारी राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए चुनावी माहौल को समझने की कोशिश करते हैं।वैसे उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने में अभी वक्त है, लेकिन लखनऊ से दिल्ली तक सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। कहीं गठबंधन की गांठें मजबूत करने की कवायद चल रही है, तो कहीं सीटों की सौदेबाजी को लेकर अंदरखाने माथापच्ची हो रही है। कोई पिछड़ों के सहारे सत्ता का रास्ता तलाश रहा है, कोई दलित-मुस्लिम समीकरण की नई इबारत लिखने में जुटा है, तो कोई अपने पुराने सामाजिक समीकरण को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है।

देखा जाये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का मिजाज ही कुछ ऐसा है। यहां चुनाव सिर्फ लखनऊ की कुर्सी का नहीं होता, बल्कि हर जिले, हर मंडल, हर जाति और हर राजनीतिक बिरादरी के प्रभाव की परीक्षा होती है। यहां लखनऊ की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता पूर्वांचल के गांवों से भी निकलता है, पश्चिमी यूपी के खेतों से भी, बुंदेलखंड की जमीन से भी और अवध की सियासी चौपालों से भी। 2027 की लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास दोहरा पाएगी? या फिर अखिलेश यादव विपक्ष को एकजुट करके भाजपा के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी करेंगे? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस इस बार सपा के साथ सीटों का ऐसा तालमेल बना पाएगी, जिसमें दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बची रहें और गठबंधन की जमीन भी न खिसके? और क्या ओवैसी तथा चंद्रशेखर आजाद का नया मोर्चा यूपी की राजनीति में कोई नया अध्याय लिख पाएगा? सबसे पहले भाजपा के घर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए का कुनबा पहले के मुकाबले बड़ा हुआ है। भाजपा के साथ अपना दल (सोनेलाल), निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे दल जुड़े हुए हैं। हर सहयोगी दल की अपनी जातीय और क्षेत्रीय राजनीतिक जमीन है। किसी की नजर पूर्वांचल पर है, किसी का प्रभाव पश्चिमी यूपी में है, तो कोई कुर्मी, निषाद, राजभर और जाट राजनीति के सहारे अपनी हिस्सेदारी मजबूत करना चाहता है।

खबरों के मुताबिक भाजपा 2027 के चुनाव में सहयोगी दलों के लिए लगभग 60 से 70 सीटें छोड़ने के विकल्प पर विचार कर रही है। 2022 में अपना दल और निषाद पार्टी को मिलाकर केवल 27 सीटें दी गई थीं। अब आरएलडी और सुभासपा के एनडीए में शामिल होने के बाद सीटों का गणित पूरी तरह बदल गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी सहयोगी दल भाजपा के सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर राजी हो जाएंगे? ओम प्रकाश राजभर की अपनी महत्वाकांक्षा है, जयंत चौधरी की अपनी राजनीतिक जमीन है, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की अपनी मांगें हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी राजनीतिक ताकत के हिसाब से उसे हिस्सेदारी मिले। यही भाजपा के सामने सबसे बड़ी गठबंधन चुनौती है। क्योंकि राजनीति में सिर्फ मंच साझा करने से गठबंधन नहीं चलता, गठबंधन तब चलता है जब कार्यकर्ता एक-दूसरे के लिए वोट मांगने को तैयार हों। सीटों का बंटवारा हो भी गया तो असली परीक्षा जमीनी तालमेल की होगी।

अब विपक्ष के खेमे में आइए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा राजनीतिक झटका दिया था। सपा ने 37 और कांग्रेस ने छह लोकसभा सीटें जीती थीं। इस नतीजे ने विपक्ष को यह भरोसा दिया कि अगर वोटों का बिखराव रोका जाए और सामाजिक समीकरणों को एक मंच पर लाया जाए, तो मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन विधानसभा का चुनाव लोकसभा से अलग होता है। यहां 403 सीटों पर अलग-अलग उम्मीदवार, स्थानीय समीकरण, जातीय प्रभाव और संगठन की ताकत काम करती है। सबसे बड़ी मुश्किल सीटों का बंटवारा है।

कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन बढ़ाना चाहती है। वह सिर्फ कुछ सीटों पर चुनाव लड़कर संतुष्ट नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का तर्क है कि सीटों का बंटवारा संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। कांग्रेस की ओर से बड़ी संख्या में सीटों की मांग और सपा की ओर से जीतने योग्य सीटों पर जोर की खबरें सामने आती रही हैं। 13 नवंबर को अखिलेश यादव ने अपने मौजूदा सहयोगियों के साथ आगे बढ़ने की बात कही और INDIA गठबंधन को स्थायी राजनीतिक साझेदारी बताया। लिहाजा गठबंधन की संभावना बनी हुई है, लेकिन सीटों की पंचायत अभी सबसे बड़ा पेच है।

सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर 2024 वाला तालमेल दोहरा पाएंगे? अगर दोनों दलों में समझौता होता है तो विपक्ष के लिए यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आधार होगा। लेकिन अगर कांग्रेस ज्यादा सीटों पर अड़ती है और सपा अपनी शर्तों पर कायम रहती है, तो दोस्ती की परीक्षा लखनऊ की सीटों पर ही हो जाएगी। साथ ही अब इस चुनावी कहानी में सबसे नया और महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है और दोनों दलों ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। यह गठबंधन दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों को एक साझा राजनीतिक मंच देने का दावा कर रहा है।

अभियान

काशी विश्वनाथ के दर्शन से जागती है शिवभक्ति, मिलता है अक्षय पुण्य

भारत की आध्यात्मिक चेतना में काशी का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। इसे केवल एक प्राचीन नगर या तीर्थस्थल के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह ऐसी पावन भूमि मानी जाती है, जहां जीवन, मृत्यु और मोक्ष के रहस्य भगवान शिव की आराधना से जुड़ते हैं। गंगा के पवित्र तट पर बसी काशी को अनादि नगरी कहा गया है। मान्यता है कि इस नगरी के कण-कण में महादेव का वास है और यहां आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु शिवभक्ति के साथ आत्मिक शांति का अनुभव करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर इसी आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां विराजमान ज्योतिर्लिंग के दर्शन को भक्त अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं काशी को अपना प्रिय धाम बनाया है। यही कारण है कि इसे शिव की नगरी कहा जाता है। पुराणों में काशी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि यह नगरी सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है और प्रलय के समय भी भगवान शिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। इस मान्यता के कारण काशी को अविनाशी और अक्षय क्षेत्र कहा गया है। यहां की आध्यात्मिक परंपरा में यह विश्वास गहराई से जुड़ा है कि महादेव अपने भक्तों को जन्म-मरण के बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं।

काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्थान रखता है। यहां शिवलिंग के दर्शन और पूजन को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। श्रद्धालु दूर-दूर से बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य तथा शांति की कामना करते हैं। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की आवाजाही शुरू हो जाती है। घंटियों की ध्वनि, वैदिक मंत्रों का उच्चारण और हर-हर महादेव के जयकारे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। गंगा स्नान के बाद बाबा के दर्शन करना अनेक श्रद्धालु अपनी धार्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं।

काशी विश्वनाथ नाम का भी गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। विश्वनाथ अर्थात समस्त संसार के स्वामी। भगवान शिव को सृष्टि का पालन करने वाली चेतना और संहार के बाद नए सृजन का आधार माना गया है। वे देवों के देव महादेव हैं, जो अपने भक्तों के लिए सहज और करुणामय हैं। उनकी आराधना में किसी विशेष वैभव की आवश्यकता नहीं मानी जाती। एक लोटा जल, बेलपत्र, धतूरा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी उन्हें प्रिय बताई गई है। यही सरलता शिवभक्ति को आम जनमानस से जोड़ती है।

काशी की महिमा केवल विश्वनाथ मंदिर तक सीमित नहीं है। यहां गंगा के घाट, प्राचीन मंदिर, मठ, आश्रम और धार्मिक परंपराएं मिलकर एक व्यापक आध्यात्मिक वातावरण बनाते हैं। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती, मणिकर्णिका घाट की धार्मिक मान्यताएं और संकरी गलियों में बसे छोटे-बड़े शिवालय इस नगरी की विशिष्ट पहचान हैं। सुबह गंगा तट पर सूर्योदय के समय होने वाली पूजा और शाम को दीपों से जगमगाते घाट श्रद्धालुओं के मन में अद्भुत अनुभूति पैदा करते हैं। काशी में धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि यहां के रहन-सहन, लोकजीवन और संस्कृति में भी दिखाई देता है।

काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास भी उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। समय-समय पर मंदिर को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था कभी कमजोर नहीं हुई। इतिहास में मंदिर के निर्माण, पुनर्निर्माण और संरक्षण के कई प्रसंग मिलते हैं। अठारहवीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। उनका योगदान भारतीय धार्मिक धरोहरों के संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने अनेक तीर्थस्थलों के विकास और मंदिरों के पुनर्निर्माण में भी भूमिका निभाई। काशी विश्वनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप के निर्माण में उनका नाम विशेष श्रद्धा के साथ लिया जाता है।

मंदिर के शिखर पर स्वर्णमंडित कलश और छत्र इसकी भव्यता को बढ़ाते हैं। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर के लिए सोना दान किया था। उनके इस योगदान ने मंदिर की शोभा को एक नया स्वरूप दिया। देश के अलग-अलग क्षेत्रों से आए भक्तों और शासकों ने समय-समय पर इस पवित्र धाम के संरक्षण और विकास में योगदान दिया। इस प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति और सामूहिक श्रद्धा का भी प्रतीक बन गया।

पुराणों में काशी को सप्तपुरियों में एक माना गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका को मोक्षदायिनी सात पुरियों के रूप में स्मरण किया जाता है। इनमें काशी का विशेष महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि यहां भगवान शिव की कृपा से जीव को मुक्ति का

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में छोटाउदेपुर में भव्य तरीके से मनाया गया राज्यस्तरीय 'जनजातीय गौरव दिवस-2026'

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से 2283.97 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की अमूल्य भेंट
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- पहले आदिवासी समाज केवल गांवों तक पक्की सड़कों की मांग करता था, वे क्षेत्र आज हाईस्पीड कॉरिडोर से जुड़ रहे हैं
- वर्ष 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई 'वनबंधु कल्याण योजना' आदिवासियों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर बन गई
- देश में 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो अंतिम व्यक्ति को केंद्र में रखकर बनाई गई सरकारी योजनाओं का नतीजा है

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 15 नवंबर का दिन इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया : श्री नरेशभाई पटेल, आदिजाति विकास मंत्री

▸▸ राज्यभर में 86 स्थानों पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, उमरगाम से अंबाजी तक बसे 1.11 करोड़ से अधिक आदिवासी बंधुओं के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध : श्री नरेशभाई पटेल

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आज से राज्य के 14 आदिवासी बहुल जिलों में 'प्राकृतिक कृषि आधारित वाड़ी सहाय योजना' शुरू की



गांधीनगर : धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर रविवार को छोटाउदेपुर की धरती से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की दिव्य चेतना को वंदन करते हुए सभी को भगवान बिरसा मुंडा जयंती की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री आदिवासी बहुल जिले छोटाउदेपुर में 'जनजातीय गौरव दिवस' के राज्यस्तरीय गरिमामय समारोह में सहभागी हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी वीरों के बलिदान और अमूल्य योगदान को देश के समक्ष उजागर करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। वर्ष 2007 में शुरू हुई 'वनबंधु कल्याण योजना' आदिवासियों के सर्वांगीण उत्कर्ष के लिए मील का पत्थर साबित हुई है और अब अगले पांच वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की योजना बनाई गई है।

उन्होंने गर्व से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय क्षेत्रों और आदिवासियों के सर्वांगीण विकास का बीड़ा उठाया है। पहले जिन्हें कोई पूछता नहीं था, उन्हें पूजने का काम श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में 231 करोड़ रुपए के विकास कार्यों और व्यक्तिगत लाभ देकर सामाजिक-आर्थिक दिशा में एक नया कदम उठाया।

आदिवासी क्षेत्रों के शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी बदलावों का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि आज आदिवासी पट्टे में 12 साइंस कॉलेज, 2 यूनिवर्सिटी, 12 मेडिकल कॉलेज और 57 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कार्यरत हैं। इसके साथ ही, 22,500 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम और 18,800 से अधिक वन अधिकार पत्र प्रदान कर आदिवासी युवाओं और परिवारों को सशक्त बनाया गया है।

इस मौके पर आदिवासी महिलाओं और स्थानीय कारीगरों की आजीविका बढ़ाने के लिए 'शबरी बूथ' और 'जोहार कैफे' जैसी अभिनव पहल की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साफ किया कि छोटाउदेपुर को 'स्पोर्ट्स और फूड प्रोसेसिंग हब' के रूप में विकसित कर स्थानीय रोजगार के नए द्वार खोले जाएंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जो 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करने में नींव का पत्थर बनेंगे।

महान क्रांतिकारी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए राज्य के आदिजाति विकास मंत्री श्री नरेशभाई पटेल ने कहा कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी और रक्षक के रूप में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान अविस्मरणीय है। उन्होंने आगे कहा कि यह बहुत आवश्यक है कि नई पीढ़ी उनके विचारों और आदर्शों से प्रेरणा ले। उन्होंने 15 नवंबर को इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

राज्य सरकार की जनजातीय विकास नीतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उमरगाम से अंबाजी तक के पूरे आदिवासी पट्टे में बसे 1 करोड़ 11 लाख से अधिक आदिवासी बंधुओं के सर्वांगीण उत्कर्ष के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने गर्व से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार की योजनाएं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों और विचारों पर आधारित हैं।

कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्वक वंदना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के 14 आदिवासी बहुल जिलों के लोगों के लिए कुल 2283.97 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का ई-लोकार्पण और ई-शिलान्यास किया। आदिजाति विकास विभाग के सचिव श्री आलोक कुमार पांडे ने अपने संबोधन में सभी का स्वागत किया।

नववर्ष के अवसर पर दी गई इस विकास कार्यों की भेंट में आदिजाति विकास विभाग के अलावा जलापूर्ति, सिंचाई, सड़क एवं भवन विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, वन एवं पर्यावरण तथा पंचायत विभाग के नागरिकों से जुड़े कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के 18,828 लाभार्थियों को वन अधिकार पत्रों की मंजूरी तथा 1017 करोड़ रुपए के विकास कार्यों सहित अन्य प्रगतिशील परियोजनाओं की भेंट भी दी गई। साथ ही, आदर्श निवासी शाला, छात्रावास, एकलव्य मॉडल स्कूल और न्यू गुजरात रेजिडेंशियल स्कूल जैसे शैक्षणिक अवसंरचना के कार्यों के साथ ही शबरी बूथ और जोहार कैफे की योजना का भी आज से शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित राष्ट्रस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भाषण का सीधा प्रसारण देखा।

इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम में लोकसभा सांसद श्री जशुभाई राठवा, राज्यसभा सांसद डॉ. मुकेशभाई राठवा, विधायक सर्वश्री राजेन्द्रसिंह राठवा, जयंतिभाई राठवा, अभेसिंह तड़वी, पूर्व सांसद श्री नारणभाई राठवा और श्रीमती गीताबेन राठवा, आदिजाति विकास विभाग के निदेशक श्री रचित राज, जिला कलेक्टर श्रीमती गार्गी जैन और जिला विकास अधिकारी श्री ओमकारसिंह शिंदे सहित स्थानीय पदाधिकारियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में आदिवासी भाई-बहनों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

17 नवंबर को अहमदाबाद और मधुबनी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा शीतकालीन एवं त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए अहमदाबाद और मधुबनी के बीच विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09433/09434 अहमदाबाद–मधुबनी–अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 09433 अहमदाबाद–मधुबनी स्पेशल ट्रेन 17 नवंबर 2026 (मंगलवार) को अहमदाबाद से प्रातः 10:10 बजे प्रस्थान करेगी तथा 19 नवंबर (गुरुवार) को रात्रि 01:00 बजे मधुबनी पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09434 मधुबनी–अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 19 नवंबर 2026 (गुरुवार) को मधुबनी से शाम 18:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा 21 नवंबर (शनिवार) को प्रातः 07:15 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन आणंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, शिहोर, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, बीना, दमोह, कटनी मुड़वारा, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा एवं सकरी स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर श्रेणी एवं सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09433 की बुकिंग 16 नवंबर 2026 को प्रातः 08:00 बजे से सभी यात्री आरक्षण केंद्रों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी।

ट्रेन के ठहराव, समय एवं कोचों की संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर वलसाड के नानापोंढा में 'जनजातीय गौरव दिवस' का शानदार आयोजन

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भव्य रैली का शुभारंभ किया



गांधीनगर : भारत के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत रविवार, 15 नवंबर की सुबह वलसाड जिले के नानापोंढा में पूरी भव्यता और उत्साहपूर्वक 'जनजातीय गौरव दिवस' मनाया गया।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने सुबह नानापोंढा सर्कल में भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर भावपूर्वक पुष्प अर्पित कर और माला पहनाकर इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की।

इसके बाद, नानापोंढा सर्कल से मुख्य कार्यक्रम स्थल हेलिपैड ग्राउंड तक एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में परंपरागत आदिवासी संस्कृति की झलक के साथ लोकनृत्यों और वाद्ययंत्रों की धुन पर बड़ी संख्या में आदिवासी भाई-बहन उत्साहपूर्वक शामिल हुए। समूचा वातावरण आदिवासी अस्मिता और गौरव के नाद से गूंज उठा।

रैली के दौरान उप मुख्यमंत्री भी आदिवासी नृत्य में शामिल हुए।

इस रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, आदिवासी समाज के अग्रणी और पदाधिकारी मौजूद रहे।

पश्चिम रेलवे मुंबई सेंट्रल एवं उधना से वन-वे स्पेशल ट्रेनें चलाएगी

यात्रियों की सुविधा के लिए तथा त्योहारी सीजन के दौरान अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे 16 नवंबर, 2026 को मुंबई सेंट्रल से अयोध्या कैंट तथा उधना से छपरा के लिए विशेष किराये पर दो वन-वे स्पेशल ट्रेनें चलाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विवरण इस प्रकार है।

1. ट्रेन संख्या 09141 मुंबई सेंट्रल–अयोध्या कैंट स्पेशल सोमवार, 16 नवंबर, 2026 को मुंबई सेंट्रल से 10.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 21.00 बजे अयोध्या कैंट पहुँचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा जं., रतलाम जं., नागदा जं., कोटा जं., सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना जं., ईदगाह आगरा जं., टूंडला जं., कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग और बाराबंकी जं. स्टेशनों पर ठहरेगी।

2. ट्रेन संख्या 09115 उधना–छपरा स्पेशल सोमवार, 16 नवंबर, 2026 को उधना से 19.45 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन, बुधवार, 18 नवंबर, 2026 को 07.30 बजे छपरा पहुँचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में व्यारा, नंदुरबार, दोंडाइचा, अमलनेर, धरणगांव, भुसावल जं., खंडवा जं., इटारसी जं., जबलपुर, कटनी जं., सतना जं., मानिकपुर जं., प्रयागराज छिवकी जं., मिर्जापुर, वाराणसी जं., जौनपुर जं., शाहगंज जं., आजमगढ़, मऊ जं., रसड़ा और बलिया स्टेशनों पर ठहरेगी।

उपर्युक्त दोनों ट्रेनों में स्लीपर क्लास तथा सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच होंगे।

इन ट्रेनों की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। मार्ग के स्टेशनों पर ठहराव के समय और कोच संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं।

केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों एवं निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का किया निरीक्षण

माननीय केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने आज अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों तथा निर्माणाधीन अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों से कार्यों की वर्तमान स्थिति, निर्माण की समय-सीमा और भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक (DRM), अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) श्री प्रदीप गुप्ता, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) के CPM श्री संजीव कुमार तथा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) के परियोजना प्रबंधक श्री राजेश अग्रवाल सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।



अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए माननीय राज्य मंत्री ने स्टेशन परिसर में विकसित की जा रही आधुनिक यात्री सुविधाओं, आधारभूत संरचना, यात्री आवागमन की व्यवस्था तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली।

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकासः अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को आधुनिक एवं विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त एक एकीकृत मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत आधुनिक स्टेशन भवन, विशाल यात्री कॉनकोर्स, एलिवेटेड रोड, बेहतर प्रवेश एवं निकास व्यवस्था तथा यात्री आवागमन को सुगम बनाने के लिए विभिन्न आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे, मेट्रो एवं हाई-स्पीड रेल सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और यात्रियों को सुविधाजनक परिवहन अनुभव उपलब्ध कराना है।

इसके पश्चात माननीय राज्य मंत्री ने निर्माणाधीन अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) स्टेशन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बुलेट ट्रेन स्टेशन के निर्माण कार्यों की प्रगति, आधुनिक तकनीकी व्यवस्थाओं एवं परियोजना के विभिन्न घटकों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान NHSRCL के अधिकारियों द्वारा परियोजना की वर्तमान स्थिति और निर्माण से जुड़े प्रमुख कार्यों के बारे में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।

अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशनः मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत विकसित किया जा रहा अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन लगभग 38,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जा रहा है। यह स्टेशन मौजूदा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 10, 11 एवं 12 के ऊपर विकसित किया जा रहा है। स्टेशन में दो प्लेटफॉर्म होंगे तथा इसकी वास्तुकला अहमदाबाद की सांस्कृतिक पहचान से प्रेरित है। इसकी छत को पतंगों की आकृति तथा बाहरी स्वरूप को प्रसिद्ध सिद्दी सैयद की जाली की डिजाइन से प्रेरित किया गया है। स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, विश्राम कक्ष, रिटेल आउटलेट्स, लिफ्ट एवं एस्केलेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ इसे मौजूदा रेलवे स्टेशन और कालूपुर मेट्रो स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा।

निरीक्षण के दौरान भारतीय रेलवे के मौजूदा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन के बीच बेहतर कनेक्टिविटी एवं यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विशेष चर्चा की गई। दोनों परियोजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने तथा यात्रियों को भविष्य में एकीकृत एवं सुविधाजनक परिवहन अनुभव उपलब्ध कराने के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई।

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना के अंतर्गत बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माण गुजरात में आधुनिक परिवहन अवसंरचना को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण पहलें हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर अहमदाबाद में रेल यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी एवं परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

आर्थिक तंगी से बंद हुई अखबारी वेबसाइटों को फिर मिलेगा डिजिटल जीवन!

HPCMF की निःशुल्क ई-पेपर वेबसाइट और तकनीकी सहयोग की पहल

नई दिल्ली। डिजिटल पत्रकारिता के विस्तार के बीच छोटे और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो रही है। वर्षों से प्रिंट माध्यम में पाठकों तक अपनी बात पहुँचाने वाले अनेक प्रकाशनों के लिए वेबसाइट बनाना और उसे लगातार संचालित रखना आर्थिक रूप से कठिन होता जा रहा है। होस्टिंग, तकनीकी रखरखाव, सुरक्षा, प्रीमियम थीम और आवश्यक सॉफ्टवेयर का खर्च कई बार उनकी क्षमता से बाहर हो जाता है। नतीजतन, कुछ समाचार-पत्र अपनी वेबसाइट बंद करने को मजबूर होते हैं, जबकि कई प्रकाशन चाहकर भी डिजिटल दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाते। इसी समस्या को देखते हुए हरिश्चंद्र प्रेस क्लब एंड मीडिया फाउंडेशन (HPCMF) ने देश के पंजीकृत समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को निःशुल्क डिजिटल ई-पेपर वेबसाइट तथा तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने की पहल की घोषणा की है।

संस्था के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य आर्थिक कठिनाइयों के कारण बंद हो चुकी समाचार-पत्रों की वेबसाइटों को दोबारा शुरू करने के साथ उन प्रिंट प्रकाशनों को डिजिटल मंच उपलब्ध कराना है, जिनके पास वेबसाइट निर्माण और संचालन के लिए पर्याप्त आर्थिक या तकनीकी संसाधन नहीं हैं। प्रथम चरण में भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRGI), पूर्व में RNI, के अंतर्गत पंजीकृत समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं को शामिल किया जाएगा।

यह पहल केवल वेब होस्टिंग उपलब्ध कराने तक सीमित रखने के बजाय एक संपूर्ण तैयार वेबसाइट और उससे जुड़ी तकनीकी सुविधाएँ देने पर केंद्रित है। HPCMF के प्रस्ताव के अनुसार, इसमें वेबसाइट निर्माण और प्रारंभिक सेटअप, डिजाइन एवं थीम, आवश्यक प्लगइन और सॉफ्टवेयर का कॉन्फिगरेशन, होस्टिंग, SSL, सुरक्षा और बैकअप जैसी सुविधाएँ शामिल होंगी। जिन प्रकाशनों की वेबसाइट पहले से मौजूद थी, उनके उपलब्ध डेटा और सामग्री को नई होस्टिंग पर स्थानांतरित करने में भी तकनीकी सहायता देने का प्रयास किया जाएगा। वेबसाइट शुरू होने के बाद आवश्यक बदलावों, तकनीकी समस्याओं और रखरखाव के लिए भविष्य में भी निःशुल्क सहयोग उपलब्ध कराने की योजना है।

इस पहल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि डिजिटल उपस्थिति अब केवल बड़े मीडिया संस्थानों की जरूरत नहीं रह गई है। जिला, तहसील और छोटे शहरों से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र भी अपने नियमित पाठकों के साथ नई पीढ़ी तक पहुँचना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए वेबसाइट का खर्च केवल शुरुआत तक सीमित नहीं होता। डोमेन, होस्टिंग, सुरक्षा और तकनीकी रखरखाव पर लगातार होने वाला व्यय छोटे प्रकाशनों के सीमित बजट पर अतिरिक्त दबाव डालता है। कई बार डिजिटल मंच से होने वाली आय उसकी संचालन लागत की भरपाई भी नहीं कर पाती। ऐसे में तकनीकी संसाधनों का साझा सहयोग छोटे प्रकाशनों के लिए उपयोगी विकल्प बन सकता है।

HPCMF की इस पहल के अंतर्गत तीन प्रकार के प्रकाशनों को विशेष रूप से लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। पहला, वे समाचार-पत्र और पत्रिकाएँ जिनकी वेबसाइट आर्थिक कारणों से बंद हो चुकी है और जिन्हें फिर से शुरू करने के लिए तकनीकी सहायता चाहिए। दूसरा, वे प्रकाशन जिनकी वेबसाइट अभी चल रही है, लेकिन होस्टिंग और रखरखाव का खर्च उठाना कठिन हो रहा है। तीसरा, वे पंजीकृत प्रिंट प्रकाशन जिन्होंने अब तक आर्थिक या तकनीकी कारणों से अपनी वेबसाइट शुरू नहीं की है। संस्था छोटे, स्थानीय, जिला स्तरीय, क्षेत्रीय और स्वतंत्र प्रकाशनों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करना चाहती है।

संस्था का कहना है कि निर्धारित होस्टिंग और तकनीकी सेवाओं के लिए लाभार्थी प्रकाशनों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, डोमेन के पंजीकरण और नवीनीकरण तथा निर्धारित दायरे से बाहर की किसी तृतीय-पक्ष सेवा के संबंध में पहले से स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। आवेदन करने वाले प्रकाशनों को पंजीकरण, स्वामित्व और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। पात्रता का सत्यापन और कार्यक्रम की निर्धारित शर्तों का पालन भी आवश्यक होगा।

इस पहल का एक महत्वपूर्ण पक्ष संपादकीय स्वतंत्रता को लेकर संस्था का स्पष्ट रुख है। HPCMF के अनुसार, उसकी भूमिका वेबसाइट होस्टिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्धारित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने तक सीमित रहेगी। समाचारों का चयन, संपादकीय नीति, रिपोर्टिंग, विचार और वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री की पूरी जिम्मेदारी संबंधित प्रकाशक एवं संपादकीय टीम की होगी। संस्था का कहना है कि तकनीकी सहयोग के आधार पर किसी प्रकाशन की संपादकीय नीति या निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

HPCMF का दीर्घकालिक लक्ष्य छोटे और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है, ताकि आर्थिक संसाधनों की कमी उनकी वर्षों की पत्रकारिता और पाठकों से बने संबंधों को डिजिटल मंच पर समाप्त न कर दे। प्रथम चरण में मौजूदा और पूर्व में संचालित प्रकाशनों को प्राथमिकता देने के साथ भविष्य में इस पहल का विस्तार अन्य पात्र पंजीकृत प्रकाशनों तक करने की योजना भी बताई गई है।

इस पहल की सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने जरूरतमंद प्रकाशनों तक यह सुविधा पहुँचती है, तकनीकी सहयोग कितनी निरंतरता से मिलता है और वेबसाइट संचालन की गुणवत्ता कितनी भरोसेमंद रहती है। फिर भी छोटे समाचार-पत्रों के सामने मौजूद डिजिटल लागत की समस्या को पहचानकर उसके समाधान की दिशा में किया गया यह प्रयास महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता की पहचान केवल छपे हुए पन्नों से नहीं बनती; वह पाठकों तक पहुँचने की निरंतरता से भी बनती है। आर्थिक कठिनाई के कारण किसी प्रकाशन की वेबसाइट बंद हो जाना केवल एक तकनीकी सेवा का बंद होना नहीं, उसकी डिजिटल पहुँच का सिमटना भी है।

ऑपरेशन अमानत के तहत भावनगर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल ने यात्री का 1.20 लाख नकद से भरा बैग सुरक्षित लौटाया

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा यात्रियों के सामान की सुरक्षा एवं सहायता के लिए निरंतर सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 15 नवंबर 2026 को ऑपरेशन अमानत के तहत RPF जवानों ने ट्रेन संख्या 19120 (वेरावल–गांधीनगर) में छूटे एक यात्री के बैग को सुरक्षित बरामद कर उन्हें सुपुर्द किया। इस बैग में 1,20,000 (एक लाख बीस हजार रुपये) नकद सहित अन्य सामान रखा हुआ था।



घटनाक्रम के अनुसार, दिनांक 15 नवंबर 2026 को जूनागढ़ RPF पोस्ट को ट्रेन के TTE से सूचना प्राप्त हुई कि एक यात्री का बैग ट्रेन संख्या 19120 में छूट गया है, जिसमें 1.20 लाख नकद रखे हुए हैं। सूचना मिलते ही जूनागढ़ पोस्ट के ASI श्री जगदीश कुमार ने तत्काल जेतलसर RPF पोस्ट के ASI श्री दीपक मीना को इसकी जानकारी दी। इसके पश्चात ट्रेन के जेतलसर स्टेशन पहुंचने पर ASI श्री दीपक मीना एवं CT श्री अल्ताफ कुरेशी ने ट्रेन की जांच की। इस दौरान CT श्री अल्ताफ कुरेशी को एक काले रंग का बैग मिला। यात्री से फोन पर संपर्क कर उन्हें जेतलसर RPF कार्यालय बुलाया गया।

यात्री की पहचान श्री परबतभाई मकवाना (79 वर्ष), निवासी मालिया हाटीना, कुकस्वाड़ा, जिला जूनागढ़, गुजरात के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि वे चोरवाड़ स्टेशन से जूनागढ़ जाने के लिए उक्त ट्रेन में सवार होने पहुंचे थे। जल्दबाजी में उन्होंने अपना काले रंग का बैग ट्रेन के पीछे वाले सामान्य कोच में रख दिया और टिकट लेने के लिए नीचे उतर गए। इसी दौरान ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई और उनका बैग ट्रेन में ही छूट गया।

यात्री की उपस्थिति में बैग की जांच की गई, जिसमें 1,20,000 की पूरी नकद राशि एवं अन्य सभी सामान सुरक्षित पाए गए। इसके बाद ऑपरेशन अमानत के तहत बैग यात्री को सही-सलामत सुपुर्द कर दिया गया। अपना सामान और पूरी नकद राशि वापस मिलने पर यात्री ने रेलवे सुरक्षा बल के जवानों का हृदय से आभार व्यक्त किया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भावनगर, श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल की तत्परता एवं समन्वित प्रयासों से यात्री का खोया हुआ सामान सुरक्षित वापस मिल सका। यह कार्रवाई यात्रियों के प्रति रेलवे की सेवा भावना और जिम्मेदारी को दर्शाती है।

मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर, श्री दिनेश वर्मा ने इस सराहनीय मानवीय कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए RPF कर्मियों की सतर्कता, तत्परता एवं संवेदनशीलता की सराहना की। मंडल सुरक्षा आयुक्त, भावनगर, श्री अजय शर्मा के मार्गदर्शन में भावनगर मंडल में यात्रियों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा निरंतर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं।

भावनगर मंडल यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक रेल यात्रा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके सामान की सुरक्षा और आवश्यकता के समय हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वलसाड के नानापोंढा में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की मौजूदगी में 'जनजातीय गौरव दिवस' का भव्य आयोजन

भगवान बिरसा मुंडा जी की 151वीं जयंती पर उप मुख्यमंत्री ने आदिवासी संस्कृति, बलिदान और विकास की गाथा पर रोशनी डाली

गांधीनगर : भगवान बिरसा मुंडा जी की 151वीं जयंती यानी 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर वलसाड जिले के नानापोंढा गांव में आयोजित एक भव्य समारोह में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी मौजूद रहे। 'जय जोहार' के गगनभेदी नारे के साथ संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को देशभर में 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जो आज देश के प्रत्येक समाज के लिए गौरव का प्रतीक बन गया है।

आदिवासी समाज के बलिदान और संस्कृति को राष्ट्र की विरासत बताते हुए उप मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज के योगदान की सराहना की और कहा कि इस समाज ने केवल धरती का संरक्षण ही नहीं किया, बल्कि देश की आजादी के लिए अपने रक्त का सिंचन भी किया है। उन्होंने मानगढ़ के गोविंद गुरु, रूपसिंह नायक, मोतालाल तेजावत और दर्शनीबेन चौधरी जैसे क्रांतिकारियों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने आगे कहा कि बनासकांठा से डांग तक, 14 आदिवासी जिलों की पूर्वी पट्टी, शामलाजी का चित्र-विचित्र मेला, कवांट का मेला, डांग दरबार और नागली का रोटला (रोटी), उंबाड़ियूं (सर्दियों का एक पारंपरिक व्यंजन), बांस का अचार और उड़द की दाल जैसे पारंपरिक पौष्टिक व्यंजन हमारी जीवंत संस्कृति और प्रकृति के साथ हमारे अटूट जुड़ाव की पहचान हैं।

राज्य सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी देते हुए श्री संघवी ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत गुजरात के 1 लाख से अधिक आदिवासी परिवारों को कुल 74,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि के स्वामित्व अधिकार सौंपे गए हैं। आज के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने एक ही दिन में 18,000 से अधिक लाभार्थियों को वन अधिकार के प्रमाण पत्र और अधिकार अभिलेख (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स-आरओआर) प्रदान कर उनके घरों में दिवाली का दीया प्रज्वलित करने का काम किया है।

उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पहले की कांग्रेस सरकारों पर तीखे राजनीतिक प्रहार करते हुए कहा कि आजादी के 50-55 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस ने आदिवासी समाज के सपनों पर रोड़े अटकाने का काम किया। धरमपुर जैसे क्षेत्रों में वर्ष 2001 तक 25 से अधिक गांवों में बिजली और 50 से अधिक गांवों में पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं जानबूझकर नहीं पहुंचाई गईं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने आदिवासी समाज का केवल 'वोट बैंक' के रूप में इस्तेमाल किया। आदिवासियों को न तो वन अधिकार पत्र दिए गए और न ही भगवान बिरसा मुंडा जी को कभी याद तक किया। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने और आदिवासी समाज



के लिए अलग मंत्रालय की शुरुआत करने का काम केवल भाजपा की मोदी सरकार ने ही किया है।

वर्ष 2001 में श्री नरेन्द्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से आदिवासी क्षेत्रों में शुरू हुई विकास यात्रा के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि पहले आदिवासी क्षेत्रों में केवल 7 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल थे, जो आज बढ़कर 57 हो गए हैं। इसके अलावा, 43 नए गर्ल्स लिटरेसी रेजिडेंशियल स्कूल, 12 से अधिक मॉडल डे स्कूल, 78 नए आदर्श निवासी स्कूल, 665 आश्रम शालाएं और 22,500 स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण किया गया है। आईटीआई की संख्या 31 से बढ़कर 78 हो गई है और इनमें सीटें 5000 से बढ़ाकर 26,000 की गई हैं।

उन्होंने कहा कि पहले आदिवासी क्षेत्रों में केवल 2 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि आज 12 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं और एमबीबीएस की सीटें 220 से बढ़कर 2050 हो गई हैं। 1 करोड़ से अधिक नागरिकों की सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग की गई है। गत दो वर्षों में आयुष्मान भारत कार्ड के तहत आदिवासी परिवारों को 1764 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, क्षेत्र में आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए संचालित 108 एंबुलेंस की संख्या 336 हो गई है।

अंत में उप मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की इन सुविधाओं के परिणामस्वरूप आज आदिवासी समाज के बेटे-बेटियां पायलट, कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर और इंजीनियर बनकर विदेश की बड़ी कंपनियों तक में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार इस विकास यात्रा को और तेज गति से आगे बढ़ाने को कटिबद्ध है।

वलसाड जिला पंचायत अध्यक्ष हेतलबेन पटेल ने कहा कि आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक स्तर पर गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में राज्य सरकार मजबूत प्रयास कर रही हैं। आदिवासी समाज की गौरवशाली संस्कृति भारतीय मूल की धरोहर है। इसके अलावा, हेतलबेन पटेल ने वृक्षारोपण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार के आह्वान और अभियानों में सहयोग प्रदान कर, सभी के साथ से देश को वैश्विक स्तर पर और आगे ले जाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत बताई।

कपराड़ा के विधायक जीतूभाई चौधरी ने भगवान बिरसा मुंडा के अदम्य साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि केवल 25 वर्ष की छोटी उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़कर देश और आदिवासी समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इस महान क्रांतिकारी को अतीत की सरकारों ने भुला दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2021 में इस दिन को 'जनजातीय गौरव दिवस' घोषित कर पूरे आदिवासी समाज को गौरव और सम्मान से नवाजा है।

इस अवसर पर उन्होंने वलसाड सहित गुजरात के 14 आदिवासी बहुल जिलों में सरकार की ओर से किए जा रहे सर्वांगीण विकास का ब्योरा दिया और इस बात का विशेष तौर पर उल्लेख किया कि सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से लेकर आदिवासी विद्यार्थियों को मेडिकल जैसी उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता तक, सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रत्येक आदिवासी परिवार तक पहुंचा है, जो वर्तमान सरकार की आदिवासी कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

धरमपुर के विधायक अरविंदभाई पटेल ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र के महात्म्य पर प्रकाश डाला।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने इस मौके पर सरकार की आदिवासी समाज से जुड़ी योजनाओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सभा स्थल पर आदिवासी देवी-देवता और बिरसा मुंडा की तस्वीर का भक्तिभाव से पूजन किया गया। जिला प्रशासन, प्रदेश एसटी मोर्चा संगठन और जिला संगठन की ओर से उप मुख्यमंत्री का आदिवासी वाद्ययंत्र घांघळी और तारपू तथा वारली चित्र भेंट कर सम्मान किया गया। डॉक्टर बनी आदिवासी बेटी डॉ. श्रीदेवी माहला ने गरीब परिवार में जन्म से लेकर डॉक्टर बनने तक की यात्रा में सरकार के योगदान के बारे में सफलता की कहानी सुनाई।

उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत 6.82 करोड़ रुपए के कुल 93 कार्यों का ई-शिलान्यास और 41.49 करोड़ रुपए कुल 381 कार्यों का ई-लोकार्पण किया। साथ ही, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता का वितरण किया गया। विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले और खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। सभी ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा।

डांग और नवसारी जिले के 34 कलाकारों ने आदिवासी संस्कृति की पहचान और गौरव के प्रतीक डांगी एवं आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसे देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए।

इस अवसर पर उमरगाम के विधायक रमणलाल पाटकर, वलसाड के विधायक भरतभाई पटेल, जिला कलेक्टर नितिन सांगवान, जिला विकास अधिकारी वंदना मीणा, परियोजना प्रशासक आस्था सोलंकी, प्रदेश संगठन मंत्री सोनलबेन सोलंकी, प्रदेश एसटी मोर्चा महामंत्री महेन्द्र चौधरी, जिला संगठन प्रभारी विनय शुक्ला, जिला संगठन अध्यक्ष हेमंतभाई कंसारा, सभी नगरपालिका और तहसील पंचायतों के अध्यक्षों सहित कई गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में आदिवासी बंधु मौजूद रहे।

जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी अचानक युवा मोर्चा के पुराने साथी विपुलभाई राउत के घर पहुंचे

कार्यकर्ता के प्रति दिखाई आत्मीयता और चाय की चुस्की के साथ परिवारजनों से की बातचीत

गांधीनगर : राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी रविवार को वलसाड जिले के नानापोंढा गांव में भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित 'जनजातीय गौरव दिवस' कार्यक्रम में शामिल हुए।

कार्यक्रम पूरा होने के बाद वापस लौटते समय उप मुख्यमंत्री ने सादगी और कार्यकर्ताओं के प्रति गहरी आत्मीयता का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया। वे युवा मोर्चा के दिनों के अपने पुराने साथी कार्यकर्ता श्री विपुलभाई राउत के घर अचानक ही मिलने पहुंच गए।

श्री हर्ष संघवी ने विपुलभाई और उनके परिवार के सदस्यों के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने परिजनों के साथ हल्की-फुल्की बातचीत की और



घर पर ही चाय की चुस्की लेते हुए पुरानी यादें ताजा कीं।

पद और प्रतिष्ठा से ऊपर उठकर अपने पुराने साथी कार्यकर्ता के प्रति उप मुख्यमंत्री द्वारा दिखाए गए प्रेम और स्नेहभाव से विपुलभाई राउत और उनका परिवार भावविभोर हो गया।

2027 में चीन से आगे रहेगी भारत की विकास रफ्तार, 7.2% वृद्धि का अनुमान

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार आने वाले वर्षों में भी दुनिया का ध्यान खींच सकती है। वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैश ने वर्ष 2027 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। यह दर चीन की अनुमानित 4.5 प्रतिशत वृद्धि से काफी अधिक होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत वर्ष 2026 में भी 7.9 प्रतिशत की विकास दर के साथ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत प्रदर्शन कर सकता है, जबकि इसी अवधि में चीन की अर्थव्यवस्था 4.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। इन अनुमानों के अनुसार, भारत की विकास गति चीन के मुकाबले अधिक बनी रह सकती है और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में देश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है।

गोल्डमैन सैश की रिपोर्ट में केवल भारत और चीन ही नहीं, बल्कि अमेरिका तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर को लेकर भी अनुमान जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की अर्थव्यवस्था वर्ष 2026 में 2.3 प्रतिशत और 2027 में 2.4 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। वहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2026 में अनुमानित 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 2027 में 2.8 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। इससे संकेत मिलता है कि दुनिया की आर्थिक गतिविधियों में अगले वर्ष मामूली सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि, अलग-अलग देशों की विकास दर में अंतर बना रहेगा और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है।

भारत की अनुमानित विकास दर को वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बीच एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जहां कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की गति अपेक्षाकृत सीमित रहने का अनुमान है, वहीं भारत के लिए 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर का आकलन देश की आर्थिक संभावनाओं को रेखांकित करता है। चीन की तुलना में भारत की तेज वृद्धि का अनुमान यह भी दर्शाता है कि एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच विकास की गति में अंतर बना रह सकता है। हालांकि, ये आंकड़े भविष्य के अनुमान हैं और वास्तविक आर्थिक प्रदर्शन घरेलू मांग, निवेश, उत्पादन, रोजगार, वैश्विक व्यापार और नीतिगत परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर होने वाला वैश्विक निवेश है। गोल्डमैन सैश ने अनुमान लगाया है कि एआई से जुड़े क्षेत्रों में खर्च तेजी से बढ़ेगा। वर्ष 2026 में इस क्षेत्र पर करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर खर्च होने की संभावना है, जबकि 2027 में यह आंकड़ा बढ़कर 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। इस बढ़ोतरी में अमेरिका में हार्डवेयर क्षेत्र में होने वाला निवेश प्रमुख भूमिका निभा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में हार्डवेयर निवेश में करीब 500 अरब डॉलर की वृद्धि होने का अनुमान है। इसमें डेटा सेंटर, कंप्यूटिंग क्षमता और एआई से जुड़ी तकनीकी जरूरतों के लिए किए जाने वाले निवेश की अहम भूमिका रहेगी।

एआई तकनीक के विस्तार के साथ दुनिया भर में कंप्यूटर चिप, सर्वर, डेटा सेंटर, नेटवर्किंग उपकरण और ऊर्जा आपूर्ति की मांग बढ़ रही है। कंपनियां अपनी कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और डिजिटल सेवाओं को बेहतर करने के लिए एआई आधारित प्रणालियों में निवेश कर रही हैं। इसका असर केवल तकनीकी कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजली, निर्माण, संचार, वित्तीय सेवाओं और औद्योगिक उत्पादन जैसे क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से एआई पर होने वाला खर्च आने वाले वर्षों में वैश्विक निवेश और आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण आधार बनता दिखाई दे रहा है।

गोल्डमैन सैश रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री जान हैटजियस ने कहा कि ऊर्जा की लागत में कमी और एआई निवेश का जारी रहना वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को मजबूती दे सकता है। उनके अनुसार, वर्ष 2027 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि में एआई निवेश का योगदान करीब 0.4 प्रतिशत अंक रहने का अनुमान है। अमेरिका की विकास दर में इसका योगदान 0.6 प्रतिशत अंक तक हो सकता है। इसका अर्थ है कि एआई से संबंधित निवेश केवल तकनीकी क्षेत्र के विस्तार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापक आर्थिक वृद्धि को भी प्रभावित कर सकता है।

हैटजियस ने यह भी कहा कि वर्ष 2027 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि ठोस बनी रहने की संभावना है, लेकिन इसमें असाधारण तेजी आने की उम्मीद नहीं है। ऊर्जा लागत में कमी से उद्योगों और कारोबारों को राहत मिल सकती है, जबकि एआई क्षेत्र में निवेश नई आर्थिक गतिविधियों को गति दे सकता है। इसके बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियां पूरी तरह समाप्त नहीं होंगी।

पिछले सात-आठ वर्षों से अक्षय कुमार कूडो टूर्नामेंट के आयोजन में लगातार समय और सहयोग देकर युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बने हैं : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

जीवन में सुख, शांति और सेवा के साथ-साथ स्वास्थ्य को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए : अभिनेता अक्षय कुमार

गांधीनगर : खेल केवल शारीरिक क्षमता विकसित करने का जरिया नहीं है, बल्कि युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, समर्पण और आत्मरक्षा की भावना विकसित करने का भी एक सशक्त माध्यम है। गुजरात में कूडो खेल को प्रोत्साहन देने और युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित अंतरराष्ट्रीय कूडो टूर्नामेंट में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, जाने-माने अभिनेता अक्षय कुमार और महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन सह प्रबंध न्यासी डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने सहभागी होकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात के सभी युवाओं की ओर से वे अभिनेता अक्षय कुमार का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। खेल के प्रति इतनी निष्ठा और समर्पण दिखाना सचमुच में प्रेरणादायी है। सफलता और व्यस्तता के बीच भी पिछले सात-आठ वर्षों से एक भी वर्ष का विराम लिए बिना अक्षय कुमार कूडो टूर्नामेंट के आयोजन के लिए लगातार समय और सहयोग दे रहे हैं। फिल्मों की शूटिंग सहित दूसरे व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद वे हर वर्ष इस खेल के लिए समय निकालते हैं, जो खेल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने आगे कहा कि श्री अक्षय कुमार आज के युवाओं के लिए फिटनेस, अनुशासन और समर्पण के श्रेष्ठ प्रेरणास्रोत हैं। एक समय था, जब नियमित रूप से कसरत करने और दौड़ लगाने वाले युवाओं का उनके मित्र मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज फिटनेस के प्रति अक्षय कुमार प्रतिबद्धता



लाखों युवाओं को प्रेरणा दे रही है। श्री संघवी ने कहा कि सूरत से शुरू हुए इस टूर्नामेंट को, अहमदाबाद में राज्य स्तरीय आयोजन के जरिए एक व्यापक राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने के लिए गुजरात सरकार भी आवश्यक सहयोग देगी। आगामी वर्षों में सभी के सामूहिक प्रयासों से कूडो खेल को गुजरात सहित देशभर में नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा।

अभिनेता अक्षय कुमार ने इस अंतरराष्ट्रीय कूडो टूर्नामेंट के आयोजन में सहयोग देने वाले उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गत 18 वर्षों से आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट का सबसे अहम पहलू खिलाड़ियों का स्वास्थ्य और शारीरिक तंदरुस्ती है।

अक्षय कुमार ने कहा कि जीवन में सुख, शांति और सेवा के साथ-साथ स्वास्थ्य को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वस्थ शरीर होगा, तभी जीवन में दूसरे सकारात्मक कार्य कर पाएंगे। उन्होंने टूर्नामेंट के सफल आयोजन में सेवा देने वाले 300 से अधिक रेफरी, शिक्षकों और सभी खिलाड़ियों के योगदान की सराहना की। अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए अक्षय कुमार ने कहा कि बच्चों को कूडो जैसे आत्मरक्षा के खेल सीखने के लिए प्रोत्साहित करने में अभिभावकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे खेल बच्चों में अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास विकसित करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में माता-पिता के मार्गदर्शन और प्रेरणा को सफलता का अहम कारण बताया। उन्होंने मार्शल आर्ट्स को प्रत्येक विद्यार्थी के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा बनाने की इच्छा जताई और आशा भी व्यक्त की कि यह विचार देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा।

महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन और प्रबंध न्यासी डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने खिलाड़ियों और आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि जीवन में चुनौतियों के सामने झुके बिना हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी अच्छे कार्य की खुले दिल से प्रशंसा होनी चाहिए और इसके पीछे किए गए निःस्वार्थ प्रयासों को भी सराहा जाना चाहिए।

उन्होंने कूडो के खिलाड़ियों द्वारा प्रतियोगिता से पहले एक-दूसरे के प्रति दर्शाए जाने वाले सम्मान और अनुशासन की भावना को भारतीय संस्कृति के संस्कारों के साथ जोड़ते हुए इसकी प्रशंसा की। उन्होंने आगे कहा कि खेल के क्षेत्र में आपसी सम्मान और आदर की भावना बनी रहे यह स्वागतयोग्य है।

इसके अलावा, उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में 'अक्षय कुमार फाउंडेशन' के प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की, जो पिछले 15 वर्षों से महिलाओं को कुडो और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर, सक्षम और साहसिक बनाने की दिशा में ये प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

'वोट चोर' के नारे से गरमाई सियासत, राहुल गांधी की हंसी पर भाजपा का हमला

हैदराबाद। हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट' के मंच से लगे 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के राजनीतिक अभियान से जुड़े इस नारे को इटली के एक नेता द्वारा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दोहराए जाने और इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हंसने तथा तालियां बजाने के दृश्य सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने इसे देश के आंतरिक राजनीतिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने वाला घटनाक्रम बताया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। दूसरी ओर, कांग्रेस ने भाजपा की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए उसे आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया, लोकतंत्र और विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों की भारतीय राजनीति पर टिप्पणी को लेकर बहस तेज कर दी है।

विवाद की शुरुआत हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के दौरान हुई। तेलंगाना सरकार की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में कांग्रेस से जुड़े राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और दुनिया के विभिन्न देशों से आए प्रगतिशील विचारधारा के बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' के महासचिव और इतालवी नेता जियाकोमो फिलिबेक ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस के चर्चित नारे 'वोट चोर, गद्दी छोड़' को दोहराया। उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद करते हुए 'वोट थीफ, लीव योर सीट' भी कहा। उस समय मंच पर राहुल गांधी मौजूद थे और वीडियो में उन्हें इस नारे के दौरान हंसते तथा तालियां बजाते देखा गया। यही दृश्य राजनीतिक विवाद का प्रमुख आधार बन गया।

फिलिबेक ने अपने संबोधन में राहुल गांधी के चुनावी अभियान का समर्थन करते हुए 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत को लोकतंत्र की बुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मतदाता सूचियों को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने की बात उठा रहे हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग इस मुद्दे पर आवाज बुलंद कर चुके हैं। उन्होंने लोकतंत्र को ऐसी व्यवस्था बताया, जिसकी रक्षा के लिए नागरिकों और राजनीतिक दलों को लगातार प्रयास करने की जरूरत होती है। इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस के नारे को मंच से दोहराया। फिलिबेक ने भारत में लोकतंत्र को लेकर चिंता जताई और कांग्रेस तथा राहुल गांधी के साथ खड़े होने की बात कही। उनके इस संबोधन के बाद भाजपा ने इसे भारतीय राजनीति में विदेशी प्रतिनिधि की खुली दखलंदाजी करार दिया। दरअसल, 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से चुनावी प्रक्रिया तथा मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर उठाए जा रहे सवालों से जुड़ा है। कांग्रेस का आरोप रहा है कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियां हो रही हैं। राहुल गांधी इस मुद्दे को विभिन्न राजनीतिक मंचों पर उठाते रहे हैं। भाजपा और चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। ऐसे में जब यही नारा किसी विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि ने भारत के एक राजनीतिक सम्मेलन में लगाया तो भाजपा ने इसे केवल विपक्ष के राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं माना, बल्कि देश के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का मुद्दा बना दिया।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी ने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है, जो किसी विदेशी के भारत का अपमान करने पर हंस रहा हो? रिजिजू ने लिखा कि वह यह नहीं पूछ रहे हैं कि कौन सा भारतीय विदेश जाकर भारत का अपमान करता है। उनका यह बयान सीधे तौर पर उस वीडियो के संदर्भ में देखा गया, जिसमें फिलिबेक नारा लगाते दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी उनके साथ हंसते तथा तालियां बजाते नजर आ रहे हैं। भाजपा ने इस प्रतिक्रिया के जरिए यह सवाल उठाया कि भारतीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर विदेशी प्रतिनिधियों की टिप्पणियों को किस सीमा तक स्वीकार किया जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान हैदराबाद समिट का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार तीन लोकसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस हताशा में देश और विदेश से वामपंथी विचारधारा के समर्थकों को बुला रही है। शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत विरोधी विचार रखकर देश को दुनिया में बदनाम करने का काम किया है। उनके बयान के बाद भाजपा ने इस विवाद को और व्यापक राजनीतिक संदर्भ देते हुए कांग्रेस की अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियों और विदेशी प्रतिनिधियों के साथ उसके संवाद पर सवाल खड़े किए।

भाजपा का तर्क है कि भारतीय लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था से जुड़े विवादों पर देश के भीतर राजनीतिक दलों के बीच बहस हो सकती है, लेकिन विदेशी राजनीतिक नेताओं को ऐसे मुद्दों पर भारतीय सरकार और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ नारे लगाने का मंच देना उचित नहीं है। पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें ऐसे वक्त में अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करनी चाहिए थी। भाजपा नेताओं के मुताबिक, विदेशी प्रतिनिधि की ओर से लगाए गए नारे पर राहुल गांधी का हंसना और तालियां बजाना इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रूप से और संवेदनशील बनाता है।

वहीं, कांग्रेस की ओर से भाजपा की प्रतिक्रिया को राजनीतिक मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश बताया गया है। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र, चुनावी पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों पर चर्चा किसी एक देश तक सीमित विषय नहीं है। पार्टी ने भाजपा को सलाह दी है कि विदेशी प्रतिनिधि के बयान पर विवाद खड़ा करने के बजाय उसे अपने ऊपर लगे चुनावी अनियमितताओं के आरोपों पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कांग्रेस के लिए मतदाता सूची की पारदर्शिता का मुद्दा राजनीतिक अभियान का हिस्सा है, जबकि भाजपा इसे सरकार और चुनावी संस्थाओं के खिलाफ लगाए जा रहे निराधार आरोपों के रूप में देखती रही है। इस विवाद के बीच एक बड़ा सवाल यह भी उभरकर सामने आया है कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों की भागीदारी और उनके बयानों की राजनीतिक सीमा क्या होनी चाहिए। लोकतंत्र, मानवाधिकार और चुनावी पारदर्शिता जैसे विषयों पर वैश्विक स्तर पर चर्चा होती रही है, लेकिन जब ऐसी टिप्पणियां किसी देश की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था या सरकार को सीधे निशाना बनाती हैं तो उनका घरेलू राजनीति में इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है। हैदराबाद समिट में फिलिबेक के बयान के बाद यही स्थिति देखने को मिली है। एक ओर कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन के रूप में देख रही है, तो दूसरी ओर भाजपा इसे भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में विदेशी दखल के तौर पर पेश कर रही है।